



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03102025-266635
CG-DL-E-03102025-266635

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 297]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 30, 2025/आश्विन 8, 1947

No. 297]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 30, 2025/ASVINA 8, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच की शुरुआत की अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2025

मामला सं. – एडी(ओआई)-28/2025

विषय: चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित बोरोसिलिकेट टेबल और किचन ग्लासवेयर के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू की शुरुआत।

एफ. सं. 6/31/2025-डीजीटीआर.— बोरोसिल लिमिटेड (जिसे आगे 'आवेदक' कहा गया है) द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे 'प्राधिकारी' कहा गया है) के समक्ष, समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) और समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटनरोधी वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रह और क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे 'नियमावली' कहा गया है) के अनुसार, चीन जन.गण. (जिसे आगे 'संबद्ध देश' कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित बोरोसिलिकेट टेबल और किचन ग्लासवेयर (जिसे

आगे 'संबद्ध सामान' या 'विचाराधीन उत्पाद' कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने और पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए एक आवेदन-पत्र दायर किया गया है।

आवेदक ने आरोप लगाया है कि चीन जन.गण. से संबद्ध सामानों के पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग की स्थापना की वास्तविक रूप से मंदी हुई है। तदनुसार, आवेदक ने संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

1. विचाराधीन उत्पाद 'बोरोसिलिकेट टेबल और किचन ग्लासवेयर' या बोरोसिलिकेट टेबलवेयर और किचनवेयर है। विचाराधीन उत्पाद एक अंतिम-उपयोग वाला उत्पाद है जिसका उपयोग खाना पकाने, बेकिंग, परोसने और भंडारण के लिए विभिन्न रूपों में किया जाता है। विचाराधीन उत्पाद में मिक्सिंग बाउल, सर्विंग बाउल, बेकिंग डिश, ओवल डिश, केक डिश, सूफले डिश, रोस्टर डिश, ढक्कन और/या हैंडल वाला कैसरोल, ओवन बाउल, स्टोरेज कंटेनर, टी कप/मग, प्लेट, यूनो कप, कटोरी और ड्रिंकिंग ग्लास के रूप में बोरोसिलिकेट टेबल और किचन ग्लासवेयर शामिल हैं। तथापि, निम्नलिखित उत्पाद प्रकारों को उत्पाद के दायरे से स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है -

- क. जार
- ख. कैराफ़े
- ग. चाय/काँफ़ी की केतली
- घ. पानी/जूस का जग
- ङ. पानी की बोतल
- च. राउंड स्टोरेज जार
- छ. स्केयर स्टोरेज जार
- ज. ऑयल डिस्पेंसर

2. विचाराधीन उत्पाद बोरोसिलिकेट ग्लास से बना है, जिसका उत्पादन बोरिक ऑक्साइड या बोरेक्स, सिलिका सैंड, सोडा ऐश और एल्यूमिना का उपयोग करके किया जाता है। विचाराधीन उत्पाद तापरोधी और रासायनिक रोधी है। यह तापीय आघात से मुक्त है, जिससे यह अत्यधिक तापमान को सहन कर सकता है और रासायनिक अवक्षेपण से रहित होकर खाना पकाने के लिए सुरक्षित है।
3. विचाराधीन उत्पाद सीमा प्रशुल्क अधिनियम की अनुसूची- I के अध्याय 70 के अंतर्गत वर्गीकृत है और प्रशुल्क मद 7013 2800, 7013 3700, 7013 4200, 7013 4900 और 7013 9900 के अंतर्गत आयात किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।
4. आवेदक ने लागत और कीमत के संदर्भ में अंतर को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित उत्पाद नियंत्रण संख्याएँ (पीसीएन) प्रस्तावित की हैं।
 - क. बिना पैकिंग के बोरोसिलिकेट टेबल और किचन ग्लासवेयर का उत्पादन
 - ख. बिना ढक्कन और सहायक उपकरणों के पैकिंग के साथ बोरोसिलिकेट टेबल और किचन ग्लासवेयर का उत्पादन

- ग. बिना ढक्कन और सहायक उपकरणों के पैकिंग और ढक्कन के साथ बोरोसिलिकेट टेबल और किचन ग्लासवेयर का उत्पादन
- घ. बिना पैकिंग, ढक्कन और सहायक उपकरणों के साथ बोरोसिलिकेट टेबल और किचन ग्लासवेयर का उत्पादन
5. तथापि, यह उल्लेखनीय है कि आवेदक द्वारा प्रस्तावित पीसीएन (PCNs) प्राधिकरण के पास उपलब्ध आयात आंकड़ों में प्रत्यक्ष रूप से पहचान योग्य नहीं हैं। अतः, आयात आंकड़ों में उपलब्ध उत्पाद के विवरण और आवेदक के प्रस्ताव के आधार पर, प्राधिकरण ने वर्तमान प्रारंभिक कार्यवाही के उद्देश्य से निम्नलिखित पीसीएन अपनाए हैं –
- क. बोरोसिलिकेट टेबल और किचन ग्लासवेयर का उत्पादन, पैकिंग सहित, लेकिन ढक्कन और सहायक उपकरणों के बिना
- ख. बोरोसिलिकेट टेबल और किचन ग्लासवेयर का उत्पादन, पैकिंग, ढक्कन और सहायक उपकरणों सहित।
6. वर्तमान जाँच में हितबद्ध पक्षकार, इस जाँच की शुरुआत के तीस (30) दिनों के भीतर, विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और प्रस्तावित पीसीएन (यदि कोई हो) पर साक्ष्य सहित अपने अनुरोध दायर कर सकते हैं।

ख. समान वस्तु

7. आवेदक ने उल्लेख किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देश से आयातित उत्पाद के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। आवेदक द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित उत्पाद, भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, प्रकार्य एवं उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन, तथा प्रशुल्क वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। आयातित उत्पाद और आवेदक द्वारा निर्मित उत्पाद तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध सामानों के उपभोक्ता आयातित और घरेलू रूप से उत्पादित उत्पाद का परस्पर परिवर्तनीय रूप से प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार, वर्तमान जाँच के प्रयोजनों के लिए, आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद को संबद्ध देश से आयातित उत्पाद के समान वस्तु माना गया है।

ग. घरेलू उद्योग और आधार

8. यह आवेदन बोरोसिल लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने भारत में संबद्ध सामानों के उत्पादन हेतु पहला संयंत्र स्थापित किया और 28 मार्च 2024 को वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया। आवेदक ने दावा किया है कि भारत में विचाराधीन उत्पाद का कोई अन्य उत्पादक नहीं है और वह देश में संबद्ध सामानों का एकमात्र उत्पादक है।
9. आवेदक ने उल्लेख किया है कि वह संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के किसी निर्यातक या भारत में संबद्ध सामानों के किसी आयातक से संबद्ध नहीं है।
10. आवेदक ने अनुरोध किया है कि जाँच की अवधि के दौरान, उसने संबद्ध देश से संबद्ध सामानों का आयात किया। यह नोट किया जाता है कि आवेदक एक नया उत्पादक है और उसने जाँच की अवधि के दौरान ही उत्पादन शुरू किया है। चूँकि विचाराधीन उत्पाद में विभिन्न प्रकार के उत्पाद शामिल हैं, जहाँ प्रत्येक उत्पाद के लिए एक अलग साँचे की आवश्यकता होती है, इसलिए आवेदक ने शुरू में उच्च माँग वाले उत्पादों का उत्पादन किया। इस प्रकार, एक पूर्ण उत्पाद श्रृंखला की आपूर्ति करने और अपने ग्राहकों को बनाए रखने के लिए, आवेदक को संबद्ध सामानों का आयात करने के लिए बाध्य होना पड़ा। यह नोट किया जाता है कि आवेदक ने देश में संबद्ध सामानों के उत्पादन हेतु पहला संयंत्र स्थापित करने हेतु महत्वपूर्ण निवेश किया है। आवेदक का प्राथमिक ध्यान भारत में विनिर्माण पर है, न कि संबद्ध सामानों के व्यापार पर। मामले के तथ्यों पर विचार

करते हुए, यह नोट किया जाता है कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग बनने के लिए पात्र है।

11. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक भारत में समान वस्तु का एकमात्र उत्पादक है। आवेदक भारत में कुल घरेलू उत्पादन का 100% उत्पादन करता है। इसे ध्यान में रखते हुए और उचित जांच के बाद, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग है, और आवेदन-पत्र नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार के मानदंडों को पूरा करता है।

घ. संबद्ध देश

12. वर्तमान पाटनरोधी जांच में संबद्ध देश चीन जन.गण. है।

ड. जांच की अवधि

13. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 (12 महीने) है। तदनुसार, क्षति जांच की अवधि में 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, तक की अवधि और जांच की अवधि शामिल होगी।

च. कथित पाटन का आधार

सामान्य मूल्य

14. आवेदक ने यह दावा किया है कि चीन जन.गण. को एक गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और जब तक चीनी उत्पादक यह दर्शा नहीं देते कि उद्योग में बाज़ार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ विद्यमान हैं, तब तक उनके सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार किया जाना चाहिए।
15. आवेदक ने दावा किया है कि किसी उपयुक्त बाज़ार अर्थव्यवस्था, किसी तीसरे देश में लागत या कीमत से संबंधित आँकड़े या अन्य वैकल्पिक तरीकों का सहारा इस स्तर पर उपलब्ध नहीं है। तदनुसार, आवेदक ने भारत में देय कीमत, उसकी उत्पादन लागत और उचित लाभ के आधार पर, के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। आवेदक द्वारा दावा किया गया सामान्य मूल्य जांच के प्रयोजन के लिए उपयुक्त माना गया है।

निर्यात कीमत

16. संबद्ध सामानों की निर्यात कीमत, डीजी सिस्टम के आयात आंकड़ों में दर्शाए गए अनुसार, प्रत्येक संबद्ध सामानों की सीआईएफ कीमत को ध्यान में रखकर निर्धारित की गई है। कारखानागत निर्यात कीमत निकालने के लिए समुद्री मालभाड़ा, समुद्री बीमा, बंदरगाह व्यय, बैंक प्रभार, अंतरदेशीय मालभाड़ा और कमीशन के निमित्त कीमत समायोजन किए गए हैं। आवेदकों द्वारा दावा की गई निर्यात कीमत पर, जांच के प्रयोजनार्थ उपयुक्त रूप से विचार किया गया है।

पाटन मार्जिन

17. संबद्ध सामानों के सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखानागत स्तर पर की गई है, जिससे प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से ऊपर है और संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में काफी है। इस प्रकार, प्रथम दृष्टया साक्ष्य है कि संबद्ध देश से आयातित संबद्ध सामानों को निर्यातकों द्वारा भारतीय बाज़ार में पाटित किया जा रहा है।

छ. क्षति और कारणात्मक संपर्क

18. आवेदक ने प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि संबद्ध आयातों के पाटन ने देश में घरेलू उद्योग की स्थापना को वास्तविक रूप से मंद कर दिया है। आवेदकों ने दावा किया है कि संबद्ध आयात भारतीय बाज़ार में काफी कम कीमतों पर प्रवेश कर गए हैं और ये आयात घरेलू उद्योग की कीमतों की काफी कटौती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, संबद्ध आयातों की कीमतें घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और उचित बिक्री कीमत से कम हैं। आवेदकों ने दावा किया है कि यह अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करने में असमर्थ रहा और उत्पादन के प्रत्येक चरण में इसकी उत्पादन मात्रा में गिरावट आई। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग की मालसूची बढ़ी। घरेलू उद्योग को अत्यधिक हानियाँ, नकद हानियाँ और निवेश पर नकारात्मक आय हुई। यह भी

दावा किया गया है कि घरेलू उद्योग का वास्तविक निष्पादन परियोजना व्यवहार्यता विश्लेषण में उसके अनुमानित निष्पादन से कम था।

19. इसलिए, यह प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य है कि पाटित आयातों से देश में घरेलू उद्योग की स्थापना में वास्तविक मंदी हुई है।

ज. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

20. घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से दायर विधिवत प्रमाणित आवेदन-पत्र के आधार पर, तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, जो संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के पाटन, वास्तविक मंदी के रूप में घरेलू उद्योग को क्षति तथा ऐसे पाटित आयातों और क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क को प्रमाणित करता है, तथा नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारित करने के लिए और पाटनरोधी शुल्क की उचित राशि, जो यदि लगाई जाए और घरेलू उद्योग की स्थापना को वास्तविक मंदी रोकने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए पाटनरोधी जांच शुरू करते हैं।

झ. प्रक्रिया

21. इस जांच में नियमावली के नियम 6 में दिए गए सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

ञ. सूचना प्रस्तुत करना

22. सभी पत्र प्राधिकारी को dd19-dgtr@gov.in और dd18-dgtr@gov.in पर ईमेल के द्वारा भेजे जाने चाहिए जिसकी एक प्रति adv11-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@nic.in को भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का व्याख्यात्मक भाग खोजने योग्य पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फॉर्मेट में है और डाटा फाइलें एमएस-एक्सल फॉर्मेट में हैं।
23. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, संबद्ध देश की सरकार को भारत में उनके दूतावास के माध्यम से और भारत में आयातकों तथा प्रयोक्ताओं, जो संबद्ध सामानों से जुड़े हुए जाने जाते हैं, को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमाओं के भीतर सभी संगत सूचनाएं दायर कर सकें। सभी सूचनाएं इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना में निर्धारित स्वरूप और तरीके, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं के अनुसार दायर किए जाने चाहिए।
24. कोई भी अन्य हितबद्ध पक्षकार इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर इस जांच की शुरुआत द्वारा निर्धारित स्वरूप और तरीके में, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं के अनुसार वर्तमान जांच से संगत अनुरोध भी कर सकता है।
25. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को उसका अगोपनीय रूपांतर अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराना आवश्यक है।
26. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (<https://www.dgtr.gov.in/>) को नियमित रूप से देखते रहें ताकि वे जांच से संबंधित सूचना और आगे की प्रक्रियाओं से अद्यतन रहें।

ट. समय सीमा

27. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना/अनुरोध प्राधिकारी को ईमेल पत्तों dd19-dgtr@gov.in और dd18-dgtr@gov.in पर ईमेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए और जिसकी एक प्रति adv11-dgtr@gov.in और consultan-dgtr@govcontractor.in को नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार इस सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर भेजी जानी चाहिए। तथापि यह नोट किया जाए कि उपर्युक्त नियमावली की व्याख्या के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने की सूचना उस तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुई मानी जाएगी, जिस तारीख को वह निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी गई थी या संबद्ध देश उपयुक्त राजयनिक प्रतिनिधि को भेजी गई थी। यदि कोई सूचना निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अपूर्ण है तो

प्राधिकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और नियमावली के अनुसार अपने जांच परिणाम रिकॉर्ड कर सकते हैं।

28. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित की प्रकृति सहित) सूचित करें और इस अधिसूचना की उपर्युक्त समय सीमा के भीतर अपने प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोध दायर करें।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

29. जहां कोई पक्षकार कोई गोपनीय अनुरोध करता है अथवा प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय आधार पर सूचना देता है, वहां उस पक्षकार के लिए यह अपेक्षित है कि वे नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार उस सूचना का अगोपनीय रूपांतर साथ-साथ प्रस्तुत करें। इसका अनुपालन न किए जाने पर उत्तर/अनुरोध रद्द किए जा सकते हैं।
30. यह अनुरोध प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर “गोपनीय” अथवा “अगोपनीय” चिह्नित होने चाहिए। प्राधिकारी को ऐसे चिन्हों के बिना किया गया कोई भी अनुरोध “अगोपनीय” सूचना माना जाएगा, और प्राधिकारी उन अनुरोधों का निरीक्षण करने के लिए अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
31. गोपनीय रूपांतर में वह सभी सूचनाएं निहित होंगी जो स्वभावतः गोपनीय हो, और/या अन्य सूचना, जिसके बारे में ऐसी सूचना का प्रदाता गोपनीय होने का दावा करता है। ऐसी सूचना जिसके स्वभावतः गोपनीय होने का दावा किया जाता है, या जिस सूचना की गोपनीयता का दावा अन्य कारणों से किया जाता है, उसके लिए सूचना प्रदाता को दी गई सूचना के साथ एक उचित कारण विवरण भी प्रस्तुत करना होगा कि ऐसी सूचना को प्रकट क्यों नहीं किया जा सकता।
32. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर की गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर गोपनीय रूपांतर की प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय सूचना को अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त स्थान दिया जाना चाहिए (जहां सूचीकरण संभव नहीं है) और ऐसी सूचना को उचित और पर्याप्त रूप से संक्षेपित किया जाना चाहिए, जो उस सूचना पर निर्भर करता है, जिसके संबंध में गोपनीयता का दावा किया गया है।
33. अगोपनीय सार में पर्याप्त विवरण होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार को उचित रूप से समझा जा सके। तथापि, अपवादात्मक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह दर्शा सकता है कि ऐसी सूचना का सार प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, और नियमों के नियम 7 के अनुसार पर्याप्त और समुचित स्पष्टीकरण सहित कारणों का विवरण तथा प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं, कि ऐसा सार प्रस्तुत करना क्यों संभव नहीं है, प्रदान किया जाना चाहिए।
34. अन्य हितबद्ध पक्षकार, अनुरोधों के अगोपनीय रूपांतर के परिचालित होने की तारीख से सात (7) दिनों के भीतर, हितबद्ध पक्षकार द्वारा दायर अनुरोध में दावा किए गए गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।
35. गोपनीयता के दावे के संबंध में, नियमावली के नियम 7 के अनुसार, सार्थक अगोपनीय रूपांतर या पर्याप्त एवं समुचित कारण विवरण के बिना, और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
36. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध आवश्यक नहीं है या यदि सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या संक्षिप्त रूप में इसके प्रकटन को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो वह ऐसी सूचना को अनदेखा कर सकते हैं।
37. प्राधिकारी, प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट और स्वीकार होने पर, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार की विशिष्ट अनुमति के बिना किसी भी पक्षकार को इसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

38. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और साथ ही उन सभी से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें। अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर परिचालित न करने पर, किसी हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी माना जा सकता है।

ढ. असहयोग

39. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर या प्राधिकारी द्वारा इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना में निर्धारित समय के भीतर आवश्यक सूचना तक पहुंच से इनकार करता है और अन्यथा प्रदान नहीं करता है, या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम रिकॉर्ड कर सकते हैं और केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं जो वे उचित समझें।

सिद्धार्थ महाजन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General of Trade Remedies)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2025

Case No. AD (OI) – 28/2025

Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of Borosilicate Table and Kitchen Glassware originating in or exported from China PR

F. No. 6/31/2025-DGTR.—An application has been filed by Borosil Limited (hereinafter referred to as the ‘applicant’) before the Designated Authority (hereinafter referred to as the ‘Authority’), in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the ‘Act’) and the Customs Tariff (Identification, Assessment, and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the ‘Rules’), for initiation of an anti-dumping investigation and imposition of anti-dumping duty on imports of Borosilicate Table and Kitchen Glassware (hereinafter referred to as ‘subject goods’ or ‘product under consideration’), originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the ‘subject country’).

The applicant has alleged that dumped imports of the subject goods from China PR have materially retarded the establishment of the domestic industry. Accordingly, the applicant has requested for the imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods from the subject country.

A. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

1. The product under consideration is ‘Borosilicate Table and Kitchen Glassware’ or Borosilicate Tableware and Kitchenware. The product under consideration is an end-use product used for the purpose of cooking, baking, serving and storage available in various forms. The product under consideration includes borosilicate table and kitchen glassware in the form of mixing bowls, serving bowls, baking dish, oval dish, cake dish, souffle dish, roaster dish, casserole with lid and / or handle, oven bowl, storage container, tea cup / mugs, plates, uno cups,

kattori and drinking glasses. However, the following product types are expressly excluded from the product scope -

- a. Jars
 - b. Carafe
 - c. Tea / Coffee Kettle
 - d. Water / Juice Jug
 - e. Water Bottle
 - f. Round Storage Jar
 - g. Square Storage Jar
 - h. Oil Dispensers
2. The product under consideration is made from borosilicate glass which is produced using boric oxide or borax, silica sand, soda ash and alumina. The product under consideration is heat resistant and chemical resistant. It is immune to thermal shock which enables the product to withstand extreme temperatures making it safe for cooking devoid of chemical precipitation.
3. The product under consideration is classified under Chapter 70 of Schedule I to the Customs Tariff Act and are imported under tariff items 7013 2800, 7013 3700, 7013 4200, 7013 4900 and 7013 9900. The customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the product under consideration.
4. The applicant has proposed the following product control numbers (PCNs) for the purpose of the present investigation, considering the difference in terms of cost and price.
- a. Borosilicate Table and Kitchen Glassware production without packing
 - b. Borosilicate Table and Kitchen Glassware production with packing but without lids and accessories
 - c. Borosilicate Table and Kitchen Glassware production with packing and lid but without accessories
 - d. Borosilicate Table and Kitchen Glassware production with packing, lid and accessories.
5. However, it is noted that the PCNs proposed by the applicant are not directly identifiable in the import data available with the Authority. Accordingly, based on the description of the product in the import data and proposal by the applicant, the Authority has adopted the following PCNs for the purpose of present initiation -
- a. Borosilicate Table and Kitchen Glassware production with packing but without lids and accessories
 - b. Borosilicate Table and Kitchen Glassware production with packing, lid and accessories.
6. Interested parties in the present investigation may provide their comments, duly substantiated with evidence, on the scope of the product under consideration and the proposed PCNs, if any, within thirty (30) days of initiation of this investigation.

B. LIKE ARTICLE

7. The applicant has stated that there is no known difference between the product produced by the domestic industry and the product imported from the subject country. The product produced by the applicant and that imported from the subject country are comparable in terms of physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing, and tariff classification. The imported product and the product manufactured by the applicant are technically and commercially substitutable. The applicant has claimed that consumers of the subject goods are using the imported and domestically produced product interchangeably. Thus, for the purposes of the present investigation, the product produced by the applicant has been considered as “like article” to the product being imported from subject country.

C. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

8. The application has been filed by Borosil Limited. The applicant set up the first plant for production of the subject goods in India and commenced commercial production on 28th March 2024. The applicant has claimed

that there are no other producers of the product under consideration in India and it is the sole producer of the subject goods in the country.

9. The applicant has stated that it is not related to any exporter of the subject goods from the subject country or importer of the subject goods in India.
10. The applicant has submitted that during the period of investigation, it imported the subject goods from the subject country. It is noted that the applicant is a new producer and has commenced production only during the period of investigation. Since the product under consideration includes a large variety of products where each product requires a different mould, the applicant initially produced products with high demand. Thus, in order to supply a full product range and to retain its customers, the applicant was forced to import the subject goods. It is noted that the applicant has made significant investment to set up the first plant for production of subject goods in the country. The primary focus of the applicant remains on manufacturing in India, and not trading the subject goods. Considering the facts of the case, it is noted that the applicant is eligible to constitute domestic under Rule 2(b) of the Rules.
11. The Authority notes that the applicant is the sole producer of like article in India. The applicant account for 100% of the total domestic production in India. In view of the same and after due examination, the Authority notes that the applicant constitutes eligible domestic industry in terms of Rule 2(b) of the Rules, and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

D. SUBJECT COUNTRY

12. The subject country for the present anti-dumping investigation is China PR.

E. PERIOD OF INVESTIGATION

13. The period of investigation for the purpose of the present investigation is 1st April 2024 to 31st March 2025 (12 months). Accordingly, the injury investigation period will cover the period 1st April 2021 to 31st March 2022, 1st April 2022 to 31st March 2023, 1st April 2023 to 31st March 2024, and the period of investigation.

F. BASIS FOR ALLEGED DUMPING

Normal value

14. The applicant has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and unless the Chinese producers demonstrate that market economy conditions prevail in the industry, their normal value should be determined in terms of Paragraph 7 of Annexure-I to the Rules.
15. The applicant has claimed that data relating to cost or price in an appropriate market economy, a third country or recourse to other alternative methods are not available at this stage. Accordingly, the applicant has determined normal value based on the price payable in India, based on its cost of production plus reasonable profit. The normal value claimed by the applicant has been considered as appropriate for the purpose of initiation.

Export price

16. The export price of the subject goods has been determined by considering CIF price of each of the subject goods, as reported in the DG Systems import data. Price adjustments have been on account of ocean freight, marine insurance, port expenses, bank charges, inland freight and commission to arrive at the ex-factory export price. The export price claimed by the applicants has been considered as appropriate for the purpose of initiation.

Dumping margin

17. The normal value and export price of the subject goods have been compared at the ex-factory level, which *prima facie* shows that the dumping margin is above de-minimis level and is significant in respect of the product under consideration imported from the subject country. Thus, there is *prima facie* evidence that the subject goods imported from the subject country are being dumped by the exporters in the Indian market.

G. INJURY AND CAUSAL LINK

18. The applicant has provided *prima facie* evidence establishing that the dumping of the subject imports has materially retarded the establishment of the domestic industry in the country. The applicants have claimed that the subject imports have entered the Indian market at significantly low prices and that such imports are significantly undercutting the prices of the domestic industry. Further, the subject imports are priced lower than the cost of sales and the fair selling price of the domestic industry. The applicants have claimed that it was unable to fully utilize its capacities and its production volume declined at each stage of the production. As a result, the domestic industry suffered increased inventories. The domestic industry incurred significant losses, cash losses and earned negative return on investment. It has also been claimed that the actual performance of the domestic industry was lower than its projected performance in the project feasibility analysis.

19. Therefore, there is sufficient *prima facie* evidence that the dumped imports caused material retardation to the establishment of domestic industry in the country.

H. INITIATION OF ANTI-DUMPING INVESTIGATION

20. On the basis of the duly substantiated application filed by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the *prima facie* evidence submitted by the applicant, substantiating the dumping of the subject goods from the subject country, injury to the domestic industry in the form of material retardation and the causal link between such dumped imports and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree, and effect of the dumping with respect to the product under consideration originating in or exported from the subject country and to recommend the appropriate amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to prevent material retardation to the establishment of the domestic industry.

I. PROCEDURE

21. The principles as given in Rule 6 of the Rules will be followed in the present investigation.

J. SUBMISSION OF INFORMATION

22. All communication should be sent to the Authority via email at email addresses dd19-dgtr@gov.in and dd18-dgtr@gov.in, with a copy to adv11-dgtr@gov.in and consultan-dgtr@govcontractor.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.
23. The known producers/exporters in the subject country, the government of the subject country through its embassy in India, and the importers and users in India who are known to be associated with each of the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits set out below. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.
24. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.

25. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
26. Interested parties are further advised to regularly visit the official website of the Directorate General of Trade Remedies (<https://www.dgtr.gov.in>) for any updated information as well as further processes related to the investigation.

K. TIME LIMIT

27. Any information/submission relating to the present investigation should be sent to the Authority via email at email addresses dd19-dgtr@gov.in and dd18-dgtr@gov.in, with a copy to adv11-dgtr@gov.in and consultan-dgtr@govcontractor.in, within thirty (30) days from the date of receipt of this notice as per Rule 6(4) of the Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the subject country. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the Rules.
28. All interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

L. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS

29. Where any party makes any confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard. Failure to adhere to the same may lead to rejection of the response / submissions.
30. Such submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as “non-confidential” information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.
31. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
32. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
33. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

34. Other interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed in the submissions by an interested party within seven (7) days from the date of circulation of the non-confidential version of the submission.
35. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
36. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
37. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorisation of the party providing such information.

M. INSPECTION OF PUBLIC FILE

38. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties. Failure to circulate non-confidential version of submissions might lead to consideration of an interested part as non-cooperative.

N. NON-COOPERATION

39. In case any interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative, record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

SIDDHARTH MAHAJAN, Designated Authority